

[2025] 3 एस.सी.आर. 904 : 2025 आईएनएससी 381

धीरूभाई भाईलालभाई चौहान और अन्य

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 816/2016)

21 मार्च 2025

[पमिदिघनतम श्री नरसिम्हा और मनोज मिश्रा,* जेजे]

विचार के लिए बिंदु

क्या हाई कोर्ट ने अपील करने वालों के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले को पलटने में सही किया था; क्या मामले के तथ्यों के आधार पर, बिना किसी और सबूत के, अपराध स्थल पर अपील करने वालों की सिर्फ मौजूदगी ही उन्हें गैर-कानूनी भीड़ का सदस्य मानने के लिए काफी थी।

मुख्य बिंदु¹

दंड संहिता, 1860- एस. एस. 143, 147, 153ए, 295,436,332 - एक हजार से अधिक व्यक्तियों से युक्त दंगाइयों की विशाल भीड़ - घटनास्थल से छह अभियुक्त-अपीलार्थी गिरफ्तार किए गए (मूल रूप से 7 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, विचारण के दौरान एक की मृत्यु हो गई) - उच्च न्यायालय ने उन्हें विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य मानते हुए उनकी दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया - इसकी वैधता/औचित्य: अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषमुक्ति के आदेश को उलटने में गलती की -समूह संघर्षों के ऐसे मामलों में जहाँ बड़ी संख्या में व्यक्ति सम्मिलित हों, न्यायालयों पर यह गुरुतर कर्तव्य अधिरोपित होता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी निर्दोष दर्शक को सिद्धदोष न किया जाए और उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित न किया जाए।- इस प्रकार के मामलों में, न्यायालयों को सतर्क होना चाहिए और अभियुक्त या उसके द्वारा निभाई गई भूमिका के विशिष्ट संदर्भ के बिना सामान्य कथन देने वाले साक्षियों के साक्ष्य पर भरोसा करने में संकोच करना चाहिए - वर्तमान मामले में, अपीलार्थी उसी गाँव के निवासी थे जहाँ दंगे भड़के थे, इसलिए घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति स्वाभाविक है और स्वतः ही दोषारोपण योग्य नहीं है।- घटनास्थल से उनकी गिरफ्तारी उनके दोष की गारंटी नहीं है- इस बात का कोई सबूत नहीं है कि गिरफ्तारी के समय वे विनाश के उपकरण या कोई ज्वलनशील पदार्थ आदि ले जा रहे थे, जिसमें संपत्ति या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी -पीडब्ल्यू-2 और पीडब्ल्यू-4 के बयानों के अतिरिक्त, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा

* लेखक

सही रूप से खारिज कर दिया गया था, ऐसा कोई विशिष्ट साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी उकसावे, उपद्रव या हिंसा के किसी भी कृत्य में संलिप्त थे - घटनास्थल पर अपीलार्थियों की मात्र उपस्थिति, या वहां से उनकी गिरफ्तारी, यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि वे एक हजार से अधिक व्यक्तियों से युक्त विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा थे - आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है, विचारण न्यायालय का आदेश बहाल किया जाता है। [पैरा 10,14,16-18]

आपराधिक विधि - दंगे/गुटीय संघर्ष जिनमें बड़ी संख्या में व्यक्ति सम्मिलित हों - दर्शकों के संबंध में न्यायालयों का कर्तव्य - सामान्य कथन देने वाले साक्षियों के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए दर्शकों को विधि विरुद्ध जमाव के हिस्से के रूप में सिद्धदोष नहीं ठहराया जाना चाहिए:

अभिनिर्धारित: समूह संघर्षों के ऐसे मामलों में जहाँ बड़ी संख्या में व्यक्ति सम्मिलित हों, न्यायालयों पर यह गुरुतर कर्तव्य अधिरोपित होता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी निर्दोष दर्शक को सिद्धदोष न किया जाए - इस प्रकार के मामलों में, न्यायालयों को सतर्क होना चाहिए और अभियुक्त या उसके द्वारा निभाई गई भूमिका के विशिष्ट संदर्भ के बिना सामान्य कथन देने वाले साक्षियों के साक्ष्य पर भरोसा करने में संकोच करना चाहिए- जहाँ हमलावरों की संख्या बहुत अधिक हो, वहाँ साक्षियों के लिए उनमें से प्रत्येक के द्वारा निभाई गई भूमिका का सटीक वर्णन करना संभव नहीं हो सकता है -उन परिस्थितियों की विस्तृत सूची निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है जिनसे अभियुक्त के विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा होने के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सके- न्यायालयों ने सामान्यतः भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से अभियुक्त को प्रतिनिहित रूप से उत्तरदायी माना है, अन्य बातों के साथ-साथ, (क) जहाँ वह जमाव के अन्य सदस्यों के साथ हथियार या ऐसे उपकरण लेकर अपराध स्थल पर गया हो जो जमाव के उद्देश्य की पूर्ति कर सकें; और (ख) जहाँ उसने उन घटनाओं में किसी भी तरह से भाग लिया हो जो जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करती हों। बहुत बार जब अपराध स्थल एक सार्वजनिक स्थान होता है, तो जिज्ञासावश व्यक्ति अपने घरों से यह देखने के लिए बाहर निकल आते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है - ऐसे व्यक्ति केवल एक दर्शक से अधिक कुछ नहीं होते हैं, यद्यपि किसी साक्षी को वे विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा लग सकते हैं। अतः, सावधानी के नियम के रूप में, न कि कानून के नियम के रूप में, जहाँ रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य यह स्थापित करते हैं कि बड़ी संख्या में व्यक्ति उपस्थित थे, वहाँ केवल उन्हीं व्यक्तियों को सिद्धदोष ठहराना सुरक्षित हो सकता है जिनके विरुद्ध प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप हो - कभी कभी, ऐसे मामलों में, सावधानी के नियम के रूप में न कि कानून के नियम के रूप में, न्यायालयों ने बहुलता परीक्षण को अपनाया है, अर्थात्, दोषसिद्धि तभी बरकरार रखी जा सकती है जब उसे साक्षियों

की एक निश्चित संख्या का समर्थन प्राप्त हो जो घटना का सुसंगत विवरण देते हों। इसके अतिरिक्त, यदि हथियारों से लैस व्यक्तियों की एक बड़ी भीड़ लक्षित पीड़ितों पर हमला करती है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी वास्तविक हमले में भाग लें - इसलिए, ऐसी स्थिति में, न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि विचारण का सामना कर रहा अभियुक्त विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा था या केवल एक दर्शक था - ऐसा निर्धारण मामले के प्रमाणित तथ्यों पर आधारित एक अनुमानात्मक निष्कर्ष होता है। [पैरा 13,14]

उद्धृत वाद कानून

बुसी कोटेश्वर राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [2012] 9 एससीआर 1046: (2012) 12 एससीसी 711; नागरजीत अहिर बनाम बिहार राज्य (2005) 10 एस. सी. सी. 369; मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। [1964] 8 एससीआर 133: एआईआर 1965 एससी 202 :1964 एससीसी ऑनलाइन एससी 30; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दान सिंह [1997] 1 एस. सी. आर. 764: (1997) 3 एस. सी. सी. 747- संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860

मुख्य शब्दों की सूची

गैरकानूनी सभा; दंगे; बड़ी संख्या में व्यक्तियों से जुड़ी सामूहिक झड़पें; बड़ी दंगा भीड़; आम वस्तु; भगदड़; मौके पर गिरफ्तार; बरी; अपराध स्थल पर केवल उपस्थिति; मौके पर उपस्थिति; प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी; संपत्ति का विनाश; बहुलता परीक्षण; विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य; हथियार या उपकरण ले जाने वाले सभा के सदस्य; भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलाना; निर्दोष दर्शक; स्वतंत्रता से वंचित; निषेधात्मक आदेश; दर्शक; अपराध में संलिप्त भूमिका का अभाव; दोषमुक्ति का उलटा जाना।

वाद उत्पत्ति

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: क्रिमिनल अपीली संख्या 816/2016
अहमदाबाद स्थित गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 05.05.2016 के निर्णय और आदेश से, जो क्रिमिनल अपील संख्या 155/2006 एवं क्रिमिनल अपील संख्या 817/2016 में पारित किया गया।

पक्षों के लिए उपस्थिति

अपीलार्थियों के लिए अधिवक्ता:

अलपति साहित्य कृष्ण, प्रद्युम्न गोहिल, सुश्री तरुणा सिंह गोहिल, ऋषभ एन. कपाडिया, विकास सिंह।

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता:

सुश्री रुचि कोहली, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुश्री देवयानी भट्ट,
सुश्री सृष्टि मिश्रा।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

मनोज मिश्रा, जे.

1. ये दो अपीलें अहमदाबाद स्थित गुजरात उच्च न्यायालय¹ के दिनांक 05.05.2016 के एक साझा निर्णय और आदेश को चुनौती देती हैं, जो आपराधिक अपील संख्या 155/2016 (गुजरात राज्य बनाम धीरुभाई भाइलालभाई चौहान एवं 18 अन्य) में पारित किया गया था। इसके द्वारा उच्च न्यायालय ने, यद्यपि विचारण का सामना करने वाले 19 अभियुक्तों में से 12 की दोषमुक्ति को बरकरार रखा, किंतु सत्र विचारण संख्या 119/2003 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश को आंशिक रूप से उलट दिया और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता² की धारा 143, 147, 153(ए), 295, 436 और 332 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया और उन्हें विभिन्न सजाओं से दंडित किया, जो सभी एक साथ चलेंगी और जिनमें से अधिकतम एक वर्ष की है।

पृष्ठभूमि तथ्य

2. अभियोजन पक्ष का मामला, पीडब्ल्यू-1 (एक पुलिसकर्मी) द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट³ पर आधारित है, जिसके अनुसार 28.02.2002 को, जब सूचक अन्य पुलिस कर्मियों के साथ गश्त कर रहा था, तब रात्रि लगभग 22:10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि वडोद गाँव में एक भीड़ ने एक कब्रिस्तान और एक मस्जिद को घेर लिया है; जब पुलिस दल मौके पर पहुँचा और भीड़ को तितर-बितर होने का निर्देश दिया, तो भीड़ ने पथराव किया जिससे पुलिस वाहनों को क्षति पहुँची और साथ ही पुलिस कर्मी भी घायल हुए; परिणामस्वरूप, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने और गोलीबारी करने का सहारा लेना पड़ा, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई; इस अफरा-तफरी में, पुलिस ने मौके पर ही 7 व्यक्तियों को पकड़ लिया, जिनके नाम हैं: (1) धीरुभाई भाइलालभाई चौहान, (2) महेशभाई भाइलालभाई चौहान, (3) मुकेशभाई अंबालाल पटेल, (4) किरीटभाई मणीभाई पटेल, (5) रावजीभाई हरमनभाई पटेल, (6) दीपककुमार भोपालभाई नेगी और (7) संजयकुमार लक्ष्मणसिंह महिदा, जो सभी वडोद गाँव के निवासी हैं। जाँच के परिणामस्वरूप मौके पर गिरफ्तार किए गए लोगों सहित 19 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। आरोप पत्र के आधार पर संज्ञान लिया गया, जिससे सत्र विचारण संख्या 119/2003 उद्भूत हुआ।

विचारणीय न्यायालय निर्णय

3. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिन्हें यह मामला सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपा गया था, ने मुकदमा चलाया और दिनांक 11.07.2005 के निर्णय और आदेश द्वारा सभी 19 अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
4. मामले की वे मुख्य विशेषताएँ, जिन पर विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय आधारित किया, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित हैं:
 - (i) पुलिस गवाहों के बयान घिसे-पिटे थे; वे एक भी अभियुक्त की पहचान नहीं कर सके; और अपनी प्रतिपरीक्षा में वे यह खुलासा नहीं कर सके कि किस पुलिसकर्मी ने किस अभियुक्त को पकड़ा था।
 - (ii) पीडब्ल्यू-2, जिसने दंगों में अभियुक्तों की भागीदारी के बारे में गवाही दी थी, के पिछले बयानों में निम्नलिखित लोपों के संबंध में उसका सामना कराया गया: (क) वह स्थान जहाँ से उसने घटना देखी थी और (ख) सड़क पर रोशनी की उपस्थिति, जिसने उसे अभियुक्तों की पहचान करने में मदद की थी।
 - (iii) जाँच अधिकारी (पीडब्लू-20) ने अपनी जिरह के दौरान कहा था कि चश्मदीद पीडब्लू-2 के घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

उपर्युक्त बातों और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, तथा इस तथ्य को भी देखते हुए कि गिरफ्तारी के समय अभियुक्तों के पास से कुछ भी बरामद होना नहीं पाया गया था, विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया।

उच्च न्यायालय का निर्णय

5. हाई कोर्ट ने अपने फैसले के पैराग्राफ 6.08, 6.09 और 6.10 में आरोपी संख्या 8 से 19 को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, जिनका नाम न तो एफआईआर में था और न ही उन्हें मौके पर गिरफ्तार किया गया था:

“6.08. अब, जहाँ तक शेष अभियुक्तों, अर्थात् मूल अभियुक्त संख्या 8 से 19 का प्रश्न है, पीडब्ल्यू संख्या 2 और 4 के बयानों सहित रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करने पर, हमारी यह राय है कि अपराध के समय उनकी उपस्थिति को अभियोजन पक्ष द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके उचित संदेह से परे साबित किया गया नहीं कहा जा सकता। किसी अन्य पुष्टिकारी साक्ष्य के अभाव में और पूरी तरह से पीडब्ल्यू संख्या 2 और 4 के बयानों पर भरोसा करते हुए, मूल अभियुक्त संख्या 8 से 19 को सिद्धदोष ठहराना सुरक्षित नहीं है। निःसंदेह, मूल अभियुक्त संख्या 8 से 19 की कोई शिनाख्त परेड आयोजित या संपन्न नहीं की गई थी। शिकायत में पीडब्लू नंबर 1 द्वारा उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है। बाद में जांच अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जाँच के दौरान एकत्र किए गए किस

आधार और किन साक्ष्यों के आधार पर मूल अभियुक्त संख्या 8 से 19 को गिरफ्तार किया गया था, इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

6.09. पीडब्ल्यू 2 ने कहा है कि उसने वासद पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी, हालांकि, जाँच अधिकारी ने अगले दिन पीडब्ल्यू संख्या 2 द्वारा कोई शिकायत दिए जाने से इनकार किया है। उसने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसे एक अन्य मामले, यानी इसी तरह की घटना से संबंधित सत्र मामला संख्या 155/2002 में गवाह के रूप में दर्शाया गया था, हालांकि, उस मामले में उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। वर्तमान मामले में, पीडब्लू नंबर 2 ने अदालत में कुछ अभियुक्तों की पहचान की है, हालांकि, जो घटना के 2 साल बाद है। उसने कहा है कि उसने घटना और आरोपी व्यक्तियों को छत से और स्ट्रीट लाइट में देखा था। पीडब्ल्यू 2 के बयान पर विचार करते हुए, हमारी यह राय है कि 1000 से 1500 व्यक्तियों की भीड़ में, वह मूल अभियुक्त संख्या 8 से 19 की पहचान नहीं कर सकता था। यहां तक कि उनका बयान भी भौतिक विरोधाभासों से भरा हुआ है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उनका बयान 19/3/2002 को दर्ज नहीं किया गया था, हालांकि, जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका बयान 19/03/2002 को दर्ज किया गया था। उक्त पीडब्ल्यू 2 के बयान पर विचार करते हुए, हमारी यह राय है कि पीडब्ल्यू संख्या 2 के बयान पर भरोसा करना और उसके बयान के आधार पर मूल अभियुक्त संख्या 8 से 19 को सिद्धदोष ठहराना सुरक्षित नहीं है।

6.10. इसी तरह, पीडब्ल्यू संख्या 4 - रोशनशाह बाफतीशा के संपूर्ण बयान का पुनः मूल्यांकन करने पर, हमारी यह राय है कि उन्हें घटना का चश्मदीद गवाह नहीं कहा जा सकता और उनके बयान पर भरोसा करना तथा उनके बयान के आधार पर मूल अभियुक्त संख्या 8 से 19 को सिद्धदोष ठहराना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का नाम लिया है जिन्हें आरोपी के रूप में पेश भी नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में और रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर, हमारी यह राय है कि अभियोजन पक्ष अपराध के समय मूल अभियुक्त संख्या 8 से 19 की उपस्थिति और उनके भीड़ का हिस्सा होने और/या गैर-कानूनी जमाव के सदस्य होने को साबित करने में विफल रहा है। इन परिस्थितियों में, विद्वान विचारण न्यायालय ने मूल अभियुक्त संख्या 8 से 19 को दोषमुक्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।”

6. हालांकि, अभियुक्त संख्या 1 से 5 और 7 (वर्तमान अपीलकर्ता) के संबंध में, उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि चूंकि उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार किया गया था

और एफआईआर में उनके नाम भी दर्ज थे, इसलिए अपराध स्थल पर उनकी उपस्थिति उचित संदेह से परे साबित होती है। चूंकि दंगा और संपत्ति का विनाश साबित हो चुका था, इसलिए उस गैर-कानूनी जमाव का हिस्सा होने के नाते वे दोषसिद्धि के पात्र थे। घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति को पुख्ता मानने के लिए, उच्च न्यायालय ने रक्षा पक्ष के वकील द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों को दिए गए एक सुझाव पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि अभियुक्तों को तब पकड़ा गया था जब वे आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे।

7. हमने अपीलार्थियों की ओर से श्री अलापति साहित्य कृष्ण और राज्य की ओर से सुश्री रुचि कोहली को सुना है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुतियाँ

8. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यह घटना गोधरा की घटनाओं के बाद की है। स्वीकार्य रूप से, दंगा एक गाँव की सार्वजनिक सड़क पर हो रहा था, जहाँ गाँव वालों (जैसे कि अपीलकर्ता) की उपस्थिति स्वाभाविक है और इसलिए, बिना किसी अन्य पुख्ता प्रमाण के, केवल उनकी उपस्थिति के आधार पर उन्हें गैर-कानूनी जमाव का हिस्सा नहीं माना जा सकता। अन्यथा, अपीलकर्ताओं को किसी भी प्रत्यक्ष कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराने वाला ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद नहीं है, जो यह संकेत दे सके कि वे गैर-कानूनी जमाव का हिस्सा थे। इसके अलावा, उस संबंध में एकमात्र गवाह, यानी पीडब्ल्यू-2, को न केवल विचारण न्यायालय द्वारा बल्कि उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया था। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के पास विचारण न्यायालय के निर्णय को पलटने का कोई आधार या अवसर नहीं था। इससे भी अधिक, जब यह दोषमुक्ति का निर्णय था।

राज्य की ओर से दलीलें

9. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील ने दलील दी कि दंगे के मामले में, यह विशेष रूप से बताना अत्यंत कठिन है कि किस व्यक्ति ने क्या किया। इसलिए, यदि अपराध स्थल पर भीड़ के हिस्से के रूप में अभियुक्तों की उपस्थिति सिद्ध हो जाती है, तो केवल वही दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए पर्याप्त है। चूंकि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की उपस्थिति को विधिवत प्रमाणित पाया, इसलिए अपराध स्थल पर अपनी उपस्थिति के संबंध में अभियुक्तों द्वारा कोई ठोस स्पष्टीकरण न दिए जाने की स्थिति में, उन्हें दोषी ठहराने के आदेश में कोई त्रुटि नहीं निकाली जा सकती।

विश्लेषण

10. प्रतिद्वंद्वी दलीलों का विश्लेषण करने से पहले, कुछ सिद्ध तथ्यों पर प्रकाश डालना उपयोगी होगा, जो हमारी राय में, इस मामले के निर्णय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ये हैं:

- (i) विचाराधीन दंगे रात के घंटों के दौरान हुए थे जब वहां कर्फ्यू के कोई आदेश लागू नहीं थे। दंगाई भीड़ बहुत बड़ी थी, जिसमें एक हजार से अधिक लोग शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलानी पड़ीं, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई।
 - (ii) इतने सारे लोगों में से, केवल सात लोगों को एफआईआर में नामजद किया गया था क्योंकि उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार किया गया था; और उन सात लोगों में से, उच्च न्यायालय ने छह को दोषी ठहराया क्योंकि उनमें से एक की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी।
 - (iii) यद्यपि पुलिस ने कथित तौर पर सात व्यक्तियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया था, लेकिन इस संबंध में कोई संतोषजनक साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि (क) अपनी गिरफ्तारी से पहले उन सातों ने क्या किया था, (ख) उन्हें किसने गिरफ्तार किया और कहाँ से गिरफ्तार किया। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में इस कमी को विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें दोषमुक्त करने के लिए संज्ञान में लिया गया था।
 - (iv) इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि गिरफ्तारी के समय अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के पास विनाश के कोई उपकरण थे, जैसे कि लोहे की रॉड, पत्थर, पेट्रोल या कोई ज्वलनशील पदार्थ आदि, जिनमें संपत्ति या व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने की क्षमता हो।
 - (v) पीडब्ल्यू-2 और पीडब्ल्यू-4 के बयानों को छोड़कर, जिन्हें उच्च न्यायालय ने ठोस कारणों से खारिज कर दिया था, ऐसा कोई विशिष्ट साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने उकसाने, शरारत या हिंसा के किसी भी कार्य में हिस्सा लिया था।
 - (vi) सभी अभियुक्त-अपीलार्थी उसी गाँव के निवासी हैं जहाँ दंगे हुए थे।
11. सामूहिक रूप से देखा जाए तो, उपरोक्त तथ्य यह संकेत देंगे कि दंगा करने वाली भीड़ बहुत बड़ी थी; घटना के समय तक संबंधित क्षेत्र में कर्फ्यू नहीं लगाया गया था, इसलिए उस क्षेत्र के निवासियों की आवाजाही प्रतिबंधित नहीं थी, जिसका अर्थ है कि वे अपने घर के आसपास क्या हो रहा है यह देखने के लिए बाहर निकल सकते थे; पुलिस ने रात के घंटों के दौरान हस्तक्षेप किया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए फायरिंग का सहारा लिया, जिसके परिणामस्वरूप भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। उस भगदड़ में, अपीलकर्ताओं सहित 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया, बिना उन्हें कोई विशिष्ट भूमिका सौंपे। जांच के बाद, 12 और अभियुक्तों को जोड़ा गया और अंततः, अपीलकर्ताओं सहित 19 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को सतही/लापरवाह पाया और इसलिए, सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। राज्य द्वारा दायर की गई अपील पर, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को आंशिक

रूप से पलट दिया और अपीलकर्ताओं को दंगा करने वाली गैर-कानूनी भीड़ के सदस्य के रूप में दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को गैर-कानूनी भीड़ का सदस्य इसलिए माना क्योंकि मौके पर उनकी गिरफ्तारी ने अपराध स्थल पर उनकी उपस्थिति की पुष्टि कर दी थी।

12. उस पृष्ठभूमि में, हमारे विचार के लिए जो प्राथमिक मुद्दा उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय, अपीलकर्ताओं के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय को उलटने में न्यायसंगत था। उपरोक्त मुद्दे को निर्धारित करने के लिए, हमारे विचारार्थ जो अंतर्निहित कानूनी प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों को देखते हुए, अपराध स्थल पर अपीलकर्ताओं की केवल उपस्थिति, बिना किसी अन्य कृत्य के, उन्हें गैर-कानूनी जमाव का सदस्य मानने के लिए पर्याप्त है।
13. गुटों के बीच संघर्ष के ऐसे मामलों में जहाँ बड़ी संख्या में लोग शामिल हों, अदालतों पर यह सुनिश्चित करने का एक भारी कर्तव्य होता है कि किसी भी निर्दोष तमाशबीन को दोषी न ठहराया जाए और उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित न किया जाए। इस प्रकार के मामलों में, अदालतों को सतर्क रहना चाहिए और ऐसे गवाहों की गवाही पर भरोसा करने में संकोच करना चाहिए जो अभियुक्तों के विशिष्ट संदर्भ या उनके द्वारा निभाई गई भूमिका का उल्लेख किए बिना सामान्य बयान देते हैं।⁴ ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर, विशेष रूप से जब अपराध स्थल कोई सार्वजनिक स्थान होता है, तो जिज्ञासावश लोग यह देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आते हैं कि आसपास क्या हो रहा है। ऐसे व्यक्ति दर्शक से ज्यादा कुछ नहीं हैं, हालांकि एक गवाह के लिए, वे गैरकानूनी सभा का हिस्सा प्रतीत हो सकते हैं। अतः, सावधानी के नियम के रूप में, न कि विधि के नियम के रूप में, जहाँ रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य यह स्थापित करते हैं कि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, वहाँ केवल उन्हीं व्यक्तियों को दोषी ठहराना सुरक्षित हो सकता है जिनके विरुद्ध प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप लगाया गया हो।⁵ कभी-कभी, ऐसे मामलों में, सावधानी के नियम के रूप में, न कि विधि के नियम के रूप में, अदालतों ने बहुलता परीक्षण को अपनाया है, अर्थात्, दोषसिद्धि केवल तभी बरकरार रखी जा सकती है जब वह एक निश्चित संख्या में गवाहों द्वारा समर्थित हो जो घटना का एक सुसंगत विवरण देते हों।⁶
14. हालाँकि, ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ हमलावरों की एक भीड़, जो एक गैर-कानूनी जमाव के सदस्य हैं, उस जमाव के समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए हत्या करने की दिशा में आगे बढ़ती है। ऐसे मामले में, कोई भी व्यक्ति जो उस गैरकानूनी सभा का सदस्य है, समान रूप से उत्तरदायी है, भले ही उस पर हमले का कोई विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया गया हो। अन्यथा भी, जहाँ हमलावरों की संख्या बहुत अधिक हो, वहाँ गवाहों के लिए उनमें से प्रत्येक द्वारा निभाई गई भूमिका का सटीक वर्णन करना संभव

नहीं हो सकता है। इसके अलावा, यदि हथियारों से लैस व्यक्तियों की एक बड़ी भीड़ लक्षित पीड़ितों पर हमला करती है, तो यह आवश्यक नहीं है कि उन सभी को वास्तविक हमले में हिस्सा लेना ही चाहिए।⁷ इसलिए, इस तरह की स्थिति में, न्यायालय के लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह निर्धारित करना है कि मुकदमे का सामना कर रहा अभियुक्त गैर-कानूनी जमाव का हिस्सा था या केवल एक दर्शक। इस तरह का निर्धारण अनुमानित है, जो मामले के सिद्ध तथ्यों पर आधारित है। यद्यपि उन परिस्थितियों की एक विस्तृत सूची तैयार करना व्यावहारिक नहीं है जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्त एक गैर-कानूनी जमाव का हिस्सा था, फिर भी अदालतों ने सामान्यतः भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से अभियुक्त को प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी माना है, विशेष रूप से: (क) जहाँ वह जमाव के अन्य सदस्यों के साथ हथियार या ऐसे उपकरण लेकर अपराध स्थल पर पहुँचा हो जो उस जमाव के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक हो सकते थे; और (ख) जहाँ उसने उन घटनाओं में किसी भी तरह से भाग लिया हो जो उस जमाव के समान उद्देश्य को पूरा करती हों।

15. तत्काल मामले में, अपीलार्थी उसी गाँव के निवासी थे जहाँ दंगे हुए थे, इसलिए उस स्थान पर उनकी उपस्थिति स्वाभाविक है और अपने आप में दोषारोपण नहीं है। इसके अलावा, क्योंकि यह अभियोजन पक्ष का मामला ही नहीं है कि वे हथियारों या विनाश के उपकरणों के साथ आए थे। इन परिस्थितियों में, घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति एक निर्दोष तमाशबीन की हो सकती है, जिसे निषेधाज्ञा की अनुपस्थिति में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार था। ऐसी स्थिति में, उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए थे कि वे गैर-कानूनी जमाव का हिस्सा थे न कि केवल एक दर्शक। यहाँ रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है जो यह संकेत दे कि अपीलकर्ताओं ने भीड़ को उकसाया, या उन्होंने स्वयं किसी भी तरह से ऐसा कार्य किया जो उनके गैर-कानूनी जमाव का हिस्सा होने का संकेत देता हो। इस संबंध में एकमात्र साक्ष्य पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 से आया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने ठोस कारणों से उसे खारिज कर दिया है, जिन्हें यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी दृष्टि में, इसलिए, अपराध स्थल पर उनकी मात्र उपस्थिति के आधार पर, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था कि अपीलकर्ता उस गैर-कानूनी जमाव का हिस्सा थे।
16. जिरह के दौरान, प्रतिवाद पक्ष के वकील द्वारा जांच अधिकारी को दिया गया यह सुझाव कि पकड़े जाने के समय अभियुक्त आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग यह निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त उस गैर-कानूनी जमाव का हिस्सा थे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि यह एक

तमाशबीन या दर्शक के रूप में उनकी उपस्थिति की संभावना को खारिज नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ताओं के लिए किसी भी अपराधपूर्ण भूमिका के अभाव में, मौके पर उनकी गिरफ्तारी इस बात का निर्णायक प्रमाण नहीं है कि वे गैर-कानूनी जमाव का हिस्सा थे, विशेष रूप से तब जब उनसे न तो विनाश का कोई उपकरण और न ही कोई ज्वलनशील सामग्री जब्त की गई थी। इसके अलावा, पुलिस ने गोलीबारी का सहारा लिया, जिससे लोग इधर-उधर भागने लगे। उस भगदड़ में, यहाँ तक कि एक निर्दोष व्यक्ति को भी गलती से बदमाश समझा जा सकता है। इस प्रकार, घटनास्थल से अपीलार्थियों की गिरफ्तारी उनके दोष की गारंटी नहीं है। हमारी दृष्टि में, इसलिए, घटनास्थल पर अपीलकर्ताओं की मात्र उपस्थिति, या वहाँ से उनकी गिरफ्तारी, यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि वे एक हजार से अधिक लोगों के गैर-कानूनी जमाव का हिस्सा थे। उच्च न्यायालय द्वारा इसके विपरीत लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तब और अधिक लागू होता है जब सुनवाई दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध की जा रही अपील पर हो रही हो।

17. उपरोक्त सभी कारणों से, हमारा यह विचार है कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की दोषमुक्ति के आदेश को उलटने में त्रुटि की है।
18. इसलिए, अपीलों की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है, और विचारणीय न्यायालय के आदेश को बहाल किया जाता है। यदि अपीलकर्ता जमानत पर हैं, तो उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उनके जमानत मुचलके, यदि कोई हों, तो उन्हें निरस्त किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

वाद का परिणाम: अपीलों की अनुमति दी गई।

¹मुख्य बिंदु तैयार किए गए: दिव्या पांडे

1 उच्च न्यायालय

2 भारतीय दंड संहिता

3 एफआईआर

4 बुसी कोटेश्वर राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2012) 12 एस. सी. सी. 711, पैरा 11

5 नागरजीत अहिर बनाम बिहार राज्य (2005) 10 एस. सी. सी. 369, पैराग्राफ 14

6 मसाल्टी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1965 एससी 202 : 1964 एससीसी ऑनलाइन एससी 30; जिसका पालन उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दान सिंह (1997) 3 एससीसी 747 में किया गया।

7 मसाल्टी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (उपरोक्त)